हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

8 RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

वर्ष:4 अंक:238 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, मंगलवार, 02 सितंबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

पथ प्रवाह, संवाददाता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान शहीद हुए आन्दोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये और उनके आश्रित्रों तथा राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमत्री पुष्कर धामी ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों भगवान सिंह सिरौला, प्रताप सिंह, रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानन्द भट्ट और परमजीत सिंह को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक इन सभी वीर सपूतों का सदैव ऋणी रहेगा। राज्य आन्दोलन के अपने अनुभवों को याद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि कि इस घटना ने लोगों को उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हम सभी मिलकर उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें, यही उनके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3 हजार रुपये मासिक पेंशन की सुविधा भी शुरू की है, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। नए कानून के अंतर्गत चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित भी किया है। आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राज्य निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका को देखते हुए ही राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। राज्य के समग्र विकास के साथ ही प्रदेश के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले ÷समान नागरिक संहिता÷ को लागू किया है। देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके बाद लगभग 24 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है। सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों लागू किया गया है। 7 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय को हिमालय बचाओ अभियान की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि हिमालय के पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक भुवन कापड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जा राज्य मंत्री डॉ.अनिल कपूर डब्बू, सुभाष बर्थवाल, फरजाना बेगम, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, दान सिंह रावत, नंदन सिंह खड़ायत, जीवन सिंह धामी, गोपाल सिंह राणा, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, डीएफओ हिमांशु बागरी, एडीएम पंकज उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, राज्य आंदोलनकारी एवं जनता मौजूद थी।

उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य, अग्निवीरों के सम्मान और भविष्य सुरक्षित करने की पहल

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से ÷अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025÷ अधिसूचित कर दी गई। इसके तहत उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं के समूह-ग की सीधी भर्ती में वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।

सैन्य बहुल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम

सैन्य परंपराओं से जुड़े उत्तराखंड में इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा, बल्कि उनकी सेवाओं का लाभ प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को भी मिलेगा।

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण

नियमावली के तहत अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर (पीएसी), अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

पुतिन से मिले मोदी, कहा संकट में एक-दूसरे का साथ दिया है भारत और रूस ने

तियांजिन/नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की विभिन्न देशों पर आयात शुल्क लगाये जाने की घोषणा से दुनिया भर में मची उथल-पुथल के बीच सोमवार को यहां तियांजिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की और कहा कि भारत तथा रूस हमेशा कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं तथा उनकी साझेदारी दोनों देशों के साथ-साथ वैश्विक शांति, स्थिरता तथा समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

चीन की दो दिन की यात्रा के अंतिम दिन स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने तियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन(एससीओ) के राष्ट्र प्रमुखों के 25 वें सम्मेलन के समापन के बाद श्री पुतिन के साथ बातचीत में रूस-यूक्रेन संघर्ष के जल्द समाप्त होने की भी उम्मीद जतायी।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जतायी। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ संबंधों तथा नियमित संपर्क का उल्लेख करते हुए कहा,÷ हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं। इस वर्ष दिसम्बर में हमारे 23 वें शिखर सम्मेलन के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। यह हमारी एक विशेष और सामरिक साझेदारी की गइराई और व्यापकता का परिचायक है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की भारत और रूस की नीतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारी करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

आतंकवाद साझा चुनौती, इस पर दोहरा मापदंड मंजूर नहीं : मोदी

तियांजिन/नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद , अलगाववाद और उग्रवाद को विकास की राह में बड़ी बाधा करार देते हुए कहा कि शंघाई सहयोग संगठन(एससीओ) के सभी सदस्य देशों को इस मुद्दे पर दोहरा मापदंड छोड़कर मानवता के खिलाफ इस साझा चुनौती का एकजुट होकर विरोध करने के अपने दायित्व को निभाना होगा। मोदी ने सोमवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्र प्रमुखों के 25 वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता

किसी भी देश के विकास का आधार होते हैं लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद इस राह में बड़ी चुनौतियाँ हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसीलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने हमेशा एकजुटता पर बल दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले चार दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। पहलगाम आतंकवादी हमले को आतंकवाद का घिनौना चेहरा बताते हुए उन्होंने कहा, ÷ हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में, जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया उत्तराखंड के पहले साथी केंद्र का शुभारंभ

पथ प्रवाह, खटीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा में उत्तराखंड के पहले साथी केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र आईआईटी कानपुर के सहयोग से स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर आधारित होता है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। उसी कड़ी में 2023 में प्रोजेक्ट साथी की शुरुआत की गई, जिसके तहत आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों के प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं।

कोचिंग और मेंटरिंग सुविधा

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि खटीमा केंद्र में 80 छात्रों को ऑफलाइन कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक देशभर में 15 लाख और प्रदेश में 29 हजार से अधिक विद्यार्थी प्रोजेक्ट साथी से लाभान्वित हो चुके हैं। पिछले वर्ष 500 से अधिक छात्रों ने इसी प्लेटफॉर्म की मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की।

उच्च शिक्षा में नए आयाम

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही साइंस सिटी और एस्ट्रो पार्क का निर्माण कर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 9 नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपये तक का शोध अनुदान और उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन पर प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में रही बड़ी भागीदारी

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जा राज्य मंत्री डॉ. अनिल कपूर डब्बू, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, निदेशक आईआईटी कानपुर मनिंदर अग्रवाल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार समेत अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे।

मौसम विभाग के रेड अलर्ट पर लक्सर में आपदा प्रबंधन की बैठक

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार, 01 सितंबर। मौसम विभाग द्वारा जनपद में बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में लक्सर तहसील सभागार में आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी ने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहने के निर्देश दिये। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि तहसील लक्सर जलभराव की दृष्टिगत सवेंदनशील है इसके लिए यह जरूरी है कि यदि भारी वर्षा के कारण किसी भी क्षेत्र में जलभराव के स्थिति उत्पन्न होती है तो जलनिकासी के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जलनिकास का कार्य त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि भारी वर्षा के कारण यदि कोई परिसंपत्ति एवं परियोजना क्षतिग्रस्त होती है तो उसका तत्काल आंकलन करते हुए आंकलन प्रस्ताव फोटोग्राफ सहित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को उपलब्ध करने के निर्देश दिए इसके साथ ही उन्होंने किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति एवं कोई घटना गठित होने पर इसकी सूचना तत्काल जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के कंट्री रूम एवं बाढ़ चौकियों के कंट्रोल रूम में तत्काल सूचना उपलब्ध करना सुनिश्चित करे ताकि तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जलभराव के स्थिति एवं कोई घटना गठित होने पर लोगों को बनाए जाए राहत शिविर में पहुंचने की कार्यवाही सुनाश्चित की जाए इसके लिए उन्होंने सभी राहत शिवरों में खाद्य सामग्री, बिस्तर, पानी, विद्युत एवं शौचालय की व्यवस्था भी सुनाश्चित कर की जाए। उन्होंने विद्युत विभाग, जल संस्थान एवं पेयजल निगम को निर्देश दिए है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल विद्युत व्यवस्था सुचारू की जाए तथा क्षेत्र में फील्ड कर्मचारियों से झूलती तारों का भी निरीक्षण किया जाए। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि कोई भी पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने पर पेयजल आपूर्ति तत्काल सुचारू कराई जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी लक्सर सौरभ असवाल, आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, तहसीलदार लक्सर, सीओ लक्सर नताशा सिंह, डीएसओ तेजबल सिंह, एसीएमओ डॉ अनिल वर्मा, जिला पंचायत राज अधिआरी अतुल प्रताप सिंह, एनडीआरएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार,अधिशासी अभियंता यूपीसीएल देवेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी विमल कुमार, तहसीलदार लक्सर प्रताप सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

वाहन पर पहाड़ी से मलबा गिरा, दो लोगों की मौत , कई घायल

रुद्रप्रयाग/देहरादून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में सोमवार को एक वाहन पर पहाड़ी से मलबा गिरने से दो लोगों की मौत हो गयी तथा अन्य कई घायल हो गए।

अभी तक वाहन से दो शव निकाले जा चुके हैं। जबकि तीन गंभीर घायलों को हाई सेंटर और अन्य को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। वाहन में कुल ग्यारह (11) यात्री सवार थे।

राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) के सेनानायक (कमांडेंट) अर्पण यदुवंशी ने बताया कि आज प्रातः लगभग 7ञ्34 बजे मुनकटिया क्षेत्र में एक वाहन के ऊपर अचानक मलबा गिरने से उसमें सवार 11 लोग प्रभावित हुए। इस हादसे में दो व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। जबकि ती लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने सोनप्रयाग भेजा है। जहां से दो गंभीर घायलों को उच्चतर केंद्र रेफर किया गया है।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं। फाटा, सोनप्रयाग एवं गुप्तकाशी से कुल 4 एंबुलेंस (108 एवं अन्य) मौके पर सक्रिय की गई।सभी घायलों का उपचार एमआरपी सोनप्रयाग में डॉ. प्रियंका, डॉ. गौरव एवं डॉ. जयदीप अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। गंभीर घायलों एवं मृतकों को आवश्यक कार्यवाही उपरांत जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है।

एक नजर

मसूरी गोलीकांड की बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का नमन

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी की पूर्व संध्या पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि शहीदों ने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी कांड और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ–ये तीनों दिन राज्य के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड उनकी आहुति को सदैव स्मरण करेगा और उनके आदर्शों के अनुरूप राज्य के निर्माण के लिए कार्य करता रहेगा।

बैंक और ज्वैलरी शॉप पर हरिद्वार पुलिस की सतर्क नजर

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, बैंक और ज्वैलरी शॉप पर हरिद्वार पुलिस की सर्तक नजर है। पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है। पुलिस टीम न केवल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है बल्कि संदिग्धों की चेकिंग भी कर रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर जनपद के समस्त थाना/कोतवाली प्रभारी बैंक, ज्वैलरी शॉप एवं अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। इन निर्देशों के क्रम में पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। इस दौरान दुकानों में स्थापित छ्ष्टञ्जङ्क कैमरों का निरीक्षण, ज्वैलरी शॉप संचालकों के संपर्क नंबर संकलित करना, तथा पुलिस व व्यापारियों के बीच आपसी तालमेल स्थापित कर सतर्कता बढ़ाना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

भारी वर्षा के कारण फसलों की क्षति का किसानों को तत्काल दिलाएं मुआवजा: गणेश जोशी

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार 01 सितंबर, प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य कृषि अधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी समेत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपद में भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि के कारण जो भी फसलों को नुकसान होता है उसका तत्काल आंकलन करते हुए किसानों को क्षति का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि किसी भी कृषक की पशु एवं भवन सम्पत्ति को नुकसान होता है तो उसे तत्काल नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित सहायता धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को कृषि व ग्राम्य विकास विभाग की हरिद्वार में समीक्षा की। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिये है कि जनपद के अधिक से अधिक किसानों के फसलों का बीमा कराया जाये इसके लिए उन्होंने किसानों को बीमा कराने के प्रति जागरूक करने के लिए भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के

निर्देश दिये।

बागवानी के क्षेत्र में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करने और ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करते हुए उन्हें लाभावित्त करने के लिए कहा। कहा कि 2027 में कुम्भ मेला आयोजित हो रहा है, महिला समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा तैयार किये जा रहे पहाड़ी उत्पादों का कुंभ मेले में अधिक से अधिक स्टॉल लगाये जाए। उन्होंने जनपद की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए महिला समूहों को एनआरएलएम द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनसे बेहतर संवाद करने के लिए कहा। जनपद में महिला समूहों द्वारा तैयार कराये जा उत्पादों की जानकारी ली तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को उपलब्ध कराये गये आवास की जानकारी ली। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना भी की।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने जनपद में भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति का आंकलन करते हुए किसानों को उपलब्ध कराये गये मुआवजा राशि के सम्बन्ध कृषि मंत्री को अवगत कराया। बताया कि जनपद में 44 किसानों के फसलों को क्षति हुई है जिसका आंकलन किया गया है तथा उन्हें 2 लाख 5 हजार 417 रू0 की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। तथा जनपद में तीन पशुओं की मृत्यु हुई है उन पशुपालकों को सहायता धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। तथा 09 पशुपालकों गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है 27 हजार की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। तथा जनपद में अहितुक सहायता, गृह अनुदान, अनुगृह, फसल क्षति, पशुशाला क्षति के लाभार्थीयों को कुल 16 लाख 37 हजार 6 सौ रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद के 9 हजार एक सौ एक लाभार्थीयों को आवास उपलब्ध कराये गये है तथा द्वितीय चरण में आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु 29 हजार 7 सौ 12 लोगों का सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने अवगत कराया है कि लखपति दीदी योजना के तहत जनपद में 23 हजार एक सौ बारह महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। उन्होंने कृषि मंत्री को आश्वत किया है कि उनके द्वार जो भी दिशा-निर्देश दिये गये है उनका सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

बैठक परियोजना निदेशक केएम तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेदप्रकाश, मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भण्डारी, जिला उद्यानन अधिकारी तेजपाल सिंह, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी मीरा रावत, जिला महामंत्री भाजपा आशु चौधरी, अरूण चौहान, अभिषेक गौड़ सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहें।

सीएलएफ पदाधिकारियों के साथ बैठक, नारसन में वे–साइड अमीनिटीज पर सहमति

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, 01 सितंबर। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे के निर्देशों के अनुपालन में सोमवार को नारसन विकासखंड के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नारसन विकासखंड के सकौती गांव में प्रस्तावित वे साइड अमीनिटीज (सड़क किनारे यात्री सुविधा केंद्र) के निर्माण पर चर्चा करना था। बैठक में विकासखंड की समस्त क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के पदाधिकारी शामिल हुए।

जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना ने सीएलएफ पदाधिकारियों को वे साइड अमीनिटीज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने

बताया कि इस परियोजना के तहत किन-किन कार्यों को किया जाएगा और फंड का उपयोग कैसे होगा। यह सुविधा केंद्र यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के केंद्र लोगों को साफ-सुथरे वातावरण के साथ-साथ शौचालय, पार्किंग, जलपान और स्थानीय उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं। यह केंद्र स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

इस परियोजना के लिए फंड के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सीएलएफ के पदाधिकारियों ने इस परियोजना को लेकर अपनी उत्सुकता दिखाई और इसे सफल बनाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना, डीटीई सूरज रतूड़ी, खंड विकास अधिकारी सुभाष सैनी, सहायक प्रबंधक आजीविका शिवशंकर बिष्ट, समस्त सीएलएफ के तीनों पदाधिकारी, सीएलएफ के समस्त स्टाफ, एम एंड ई राशिद, बीएमएम प्रशांत, आजीविका समन्वयक हीना, एग्री एक्सटेंशन ललित और अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

फरार हुआ चेन स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह संवाददता। चेन स्नैचिंग की घटना में शामिल दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके एक साथी को पुलिस पहले ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है, आरोपी ऋतिक मौके से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक 27.08.2025 को कोतवाली गंगनहर क्षेत्रान्तर्गत निवासरत महिला से पीरबाबा कालोनी नहर पटरी पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोतवाली गंगनहर की 29.08.2025 को अज्ञात बदमाशों के द्वारा सोनाली पार्क के पास चैकिंग कर रही पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने का प्रयास करने पर हुई मुठभेड में पुलिस ने एक आरोपी बादल को गिरफ्तार किया गया था। जिससे महिला से छीनी गयी चेन बेचकर हिस्से में आयी नगदी 29500/ रूपये बरामद हुये थे। इस दौरान दूसरा आरोपी ऋतिक मौके से फरार हो गया था। दोनों घटनाओं में फरार चल रहे ऋतिक की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने दिनाँक 31.08.2025 को फरार आरोपी को सोनाली पार्क के पास से हिरासत पुलिस लेकर उसके कब्जे से पुलिस पार्टी पर फायर के दौरान इस्तेमाल किया गया तमंचा व महिला से छीनी गयी चेन भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी ऋतिक पुत्र राजेश निवासी ग्राम दगडोली थाना नागल जिला सहारनपुर उ0प्र0 हाल निवासी शक्ति विहार थाना गंगनहर जिला हरिद्वार का रहने वाला है।

60 लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को मिलेगा पतंजलि में निःशुल्क उपचार

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, 01 सितम्बर। भूतपर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा पतंजलि योगग्राम के मध्य ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध के तहत भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का निःशुल्क उपचार अब पतंजलि में हो सकेगा। इस अनुबंध के तहत भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों पर योग, आयुर्वेद और नेचरोपैथी में होने वाले उपचार खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। वे निःशुल्क उपचार करा सकेंगे। इससे करीब 60 लाख भूतपूर्व सैनिक और परिवार लाभान्वित होंगे।

भारतीय सेना के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और उत्तराखंड सब एरिया (जेओसी) के मेजर जनरल एमपीएस गिल और स्वामी रामदेव ने एमओयू पर हस्ताक्षर के उपरांत फाइलों का आदान-प्रदान किया। इस अवसर पर स्वामी रामदेव महाराज ने कहा कि सेना और संत एक तरह से देश की सेवा अपने-अपने तरीके से करते हैं। पतंजलि को सेना की सेवा का सौभाग्य मिला इसके लिए उन्होंने भारतीय सेना का आभार जताया।

स्वामी रामदेव ने कहा कि दुनिया के कुछ देश को छोड़ दें तो पतंजलि दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां 3000 से अधिक मरीजों की भर्ती होती है। भविष्य में इसे बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य है। हम जल्द ही मार्डन मेडिकल में भी सर्जरी करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योग और आयुर्वेद शरीर को ताकत देते हैं जबकि नेचुरोपैथी से शुद्धिकरण किया जाता है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल एमपीएस गिल ने अनुबंध ने कहा कि इस अनुबंध से 60 लाख पूर्व सैनिक सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पतंजलि योगपीठ की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसमें योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साथ-साथ एलोपैथी के समावेश से समग्र एकीकृत चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगियों को आरोग्य प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि हमेशा से नवाचार में विश्वास करता है।

आचार्य बालकृष्ण ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड निःशुल्क दिया जाएगा, जिसके तहत 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। क्षेत्रीय निदेशक, श्वष्ट॥स् देहरादून कर्नल जितेन्द्र कुमार और योगग्राम के सेवा प्रमुख स्वामी आर्यदेव ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कर्नल जितेन्द्र कुमार ने कहा कि यह पहला अवसर होगा जब सेना और पतंजलि में ईसीएचएस को लेकर करार हुआ है। कार्यक्रम का सफल संयोजन डा. संगीता सिंह ने किया। कार्यक्रम में वी.एस.एम. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सबएरिया; ब्रिगेडियर परिक्षित सिंह कमाण्डेंट मिलिट्री हॉस्पिटल, देहरादून; ब्रिगेडियर जी.एस. भाटिया कमाण्डेंट मिलिट्री हॉस्पिटल, रुड़की; ब्रिगेडियर के.पी. सिंह कमाण्डेंट बी.ई.जी. एण्ड सेन्टर, रुड़की; कर्नल एम.एस. बिष्ट, निदेशक- श्वष्ट॥स् उत्तराखण्ड, सबएरिया कर्नल सतपाल अहलावत, निदेशक - श्वष्ट॥स् पॉलीक्लीनिक, रुड़की; कमाण्डर (भारतीय जलसेना) उपेन्द्र सिंह चीमा, निदेशक श्वष्ट॥स् पॉलीक्लीनिक, रायवाला; पतंजलि की ओर से साध्वी देवप्रिया, बहन अंशुल, बहन पारूल, ब्रिगेडियर टी.सी. मल्होत्रा, भाई राकेश कुमार सहित पतंजलि योगपीठ से सम्बद्ध इकाईयों के समस्त सेवाप्रमुख एवं विभागप्रमुख; बी.एन.वाई.एस. पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

अफ़ग़ानिस्तान भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 622 हुयी, 1,555 घायल

काबुल। पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों में आये भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 622 हो गयी है। इस प्राकृतिक आपदा में 1,555 अन्य घायल हुए हैं।

गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि कुनार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 610 हो गई है और यहां 1,300 लोग घायल हुये हैं। इस आपदा में अनेक घर ध्वस्त हो गये हैं।

मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी के अनुसार, नांगरहार में 12 लोग मारे गये हैं और 255 अन्य घायल हुये हैं। यहां काफी घरों को नुकसान हुआ है।

प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, खाद्य और सहायता टीमों ने आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास तेज़ कर दिए हैं।

संपादकीय

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 : बहुध्रुवीय विश्व में भारत की संतुलनकारी कूटनीति

तियानजिन, चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन ने भारत को वैश्विक कूटनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। सात साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकातों ने विश्व राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यह सब ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% भारी शुल्क लगाए जाने से नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों में दरार आ चुकी है। इस पृष्ठभूमि में भारत का यह सक्रिय कूटनीतिक खेल न केवल अमेरिका के लिए चेतावनी है बल्कि बदलते विश्व क्रम की झलक भी देता है।ट्रम्प प्रशासन का 50% आयात शुल्क भारत के 60 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा प्रहार है। इससे वस्त्र और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान उद्योग प्रभावित हुए हैं और दशकों से बन रही अमेरिका-भारत की निकटता कमजोर पड़ी है। साथ ही, रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की दोहरी नीति ने भारत की असंतोष की भावना को और गहरा किया है, जिससे बीजिंग और मॉस्को को भारत को लुभाने का अवसर मिल गया।

भारत-चीन वार्ता :मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात 2020 के गलवान संघर्ष के बाद जमी बर्फ पिघलाने का संकेत थी। दोनों नेताओं ने सीमा पर तनाव कम करने, हवाई संपर्क बहाल करने, धार्मिक यात्रा मार्ग खोलने और व्यापार आसान बनाने पर सहमति जताई। हालांकि सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है, जिससे भारत का रुख सतर्क और व्यवहारिक बना हुआ है।

भारत-रूस वार्ता : पुतिन के साथ मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने रिश्तों की मजबूती को फिर रेखांकित किया। छूट पर मिलने वाला रूसी तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। दोनों नेताओं की गाड़ी में साझा यात्रा और गले मिलना इस बात का प्रतीक था कि रूस के चीन-निर्भर होते जाने के बावजूद भारत-रूस का रिश्ता कायम है।

अमेरिका के लिए निहितार्थ

यह शिखर सम्मेलन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का स्पष्ट संदेश था। क्वाड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत) का सदस्य होते हुए भी नई दिल्ली ने बीजिंग और मॉस्को के साथ संवाद बढ़ाकर यह साबित किया कि वह किसी एक धुरी का मोहरा नहीं बनेगा। रूस ने रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय मंच को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि चीन ने तुर्की, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक को मंच पर बुलाकर अपनी बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना को मजबूती दी।

हालांकि भारत-पाकिस्तान तनाव, सदस्य देशों के परस्पर विरोधी हित और ठोस परिणामों के अभाव के कारण एससीओ (SCO) की सीमाएँ भी साफ हैं। वर्तमान परिदृश्य में यह मंच अभी अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था का वास्तविक विकल्प बनेगी, इस पर अभी संशय है। भारत के लिए यह सम्मेलन चीन-रूस खेमे में झुकने से ज्यादा अपने विकल्पों को विस्तृत करने की रणनीति रहा।वर्तमान परिपेक्ष में शंघाई शिखर सम्मेलन 2025 कोई नया विश्व क्रम गढ़ता नहीं दीखता, लेकिन यह दिखाता है कि मौजूदा व्यवस्था चुनौती के दौर में है। अमेरिका के लिए सबक यह है कि शुल्क और दबाव जैसी नीतियां उसके साझेदारों को दूर कर सकती हैं। वहीं, भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वह किसी शक्ति का प्यादा नहीं, बल्कि वह धुरी है जो बदलते वैश्विक समीकरणों को आकार दे सकती है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-बच्चों के भविष्य की गारंटी : अन्यफ राज्यों के लिए है सबक

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने हाल ही में विधानसभा से 'उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025' पारित कर एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी गूंज केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यक अधिकारों की बहस को नई दिशा देती हुई दिखाई दे रही है। ये सबक है अन्यद राज्यों के लिए जो इच्छू शक्ति के अभाव में अपने के सभी बच्चों। के हित में इस तरह के प्रभावी निर्णय लेने से बचते आए हैं।

दरअसल, यह विधेयक केवल मुस्लिम मदरसों तक सीमित न रहकर सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को भी अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करता है। अब तक की स्थिति में अल्पसंख्यक शिक्षा का दायरा संकुचित था और उसका लाभ लगभग एक ही समुदाय (मुस्लिएम) तक सीमित होकर रह गया था, किंतु धामी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता, पारदर्शिता और अवसर की भावना स्थापित होना बहुत जरूरी है, यह राज्यल के सभी बच्चोंच के हित में है।

देश भर की सच्चालई : अधिकार और वास्तविकता का अंतर

भारतीय संविधान ने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार तो दिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से राज्यों ने इस अधिकार को पूरी तरह से संतुलित ढंग से लागू अब तक नहीं किया जा सका है। देखने में यही आता है कि मदरसा अधिनियम अधिकांश राज्यों में बने, किंतु सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अपने संस्थानों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करते रहे। उनके पास न तो स्पष्ट वैधानिक मंच था और न ही अनुदान या मान्यता की प्रक्रिया में पारदर्शिता। परिणाम स्वूप अल्पउसंख्यतक के नाम पर जो भी हो रहा है, वह अधिकांशत- एक रिलीजन तक ही सीमित होकर रह गया। ऐसे में उत्तराखण्ड का यह विधेयक इसी विसंगति को दूर करता है।

इसके माध्यम से पहली बार सभी अल्पसंख्यक संस्थान एक समान छतरी तले आएंगे। अब न केवल मदरसों को बल्कि गुरुद्वारों के अधीन चल रहे विद्यालयों, ईसाई मिशनरी स्कूलों, जैन और बौद्ध समाज के संस्थानों को भी वह अधिकार प्राप्त होगा जो अब तक केवल मुस्लिम संस्थानों तक सीमित था। यह व्यापक दृष्टि अपने आप में स्वागत योग्य है क्योंकि लोकतंत्र की असली खूबसूरती तब ही दिखती है जब सबको समान अवसर मिले।

हो गया पुराने अधिनियमों का अंत

इस विधेयक के लागू होने के बाद उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को खत्म कर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा की मान्यता अब किसी एक समुदाय विशेष के अधीन नहीं होगी, बल्कि सबके लिए समान रूप से उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। यह प्राधिकरण संस्थानों को मान्यता देने, उनके वित्तीय लेन-देन पर निगरानी रखने, और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा।

यहां यह भी तय किया गया है कि संस्थानों को सोसायटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के तहत विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक होगा और उनकी जमीन-जायदाद, बैंक खाते आदि संस्थान के नाम पर दर्ज होंगे। स्वेभाविक है कि इस प्रक्रिया के पालन से व्यावस्थाक में सुधार होगा, संस्थान्ों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

इसलिए जरूरत पड़ी, ये कदम उठाने की

धामी सरकार ने यह कदम यूं ही नहीं उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में मदरसा शिक्षा से जुड़े कई गंभीर प्रश्न सामने आए। छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ियां, मिड-डे मील में अनियमितताएं, वित्तीय पारदर्शिता की कमी और यहां तक कि अवैध मदरसों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद फंडिंग की आशंकाएं लगातार सामने आती रहीं। राज्य में लगभग 450 मदरसे आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं, किंतु 500 से अधिक मदरसों के अवैध संचालन की रिपोर्ट सामने आई। तब दिसंबर 2024 में सरकार ने इन पर बड़ी कार्रवाई की और करीब 200 अवैध मदरसे बंद कराए।

सवाल उठा कि यदि मदरसा बोर्ड सही ढंग से काम कर रहा होता तो ये अनियमितताएं कैसे होतीं? फिर भी धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को सुधार का एक लम्बो वक्तस दिया, लेकिन जब देखा कि बोर्ड की मान्यता समिति 2020 से बैठक तक न कर पाई हो, तो उसकी निष्क्रियता स्पष्ट अब पूरी तरह से स्पाष्ट हो गई। यही कारण है कि सरकार ने निर्णय लिया कि अब शिक्षा व्यवस्था को समुदाय विशेष की संकीर्ण चौखट से बाहर निकालकर व्यापक और समावेशी रूप दिया जाए। नया विधेयक उसी सोच का परिणाम है। अब शिक्षा का केंद्र बच्चे होंगे, न कि कोई खास धार्मिक पहचान।

पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा ने 20 अगस्त को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 पारित कर दिया। यह विधेयक राज्य में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ मदरसों को भी अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ प्रदान करेगा । सभी अल्पसंख्यक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यही इसका उद्देश्य है। बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन उत्तराखण्ड बोर्ड के मानकों के आधार पर होगा और कोई भी संस्थान पारदर्शिता से समझौता नहीं कर सकेगा। यदि वित्तीय अनियमितता या सामाजिक-सांप्रदायिक सौहार्द के विरुद्ध गतिविधियां पाई गईं तो मान्यता वापस ली जा सकेगी।

मुख्यमंत्री धामी कहते हैं, केन्द्रीय छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में विसंगतियां और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर मुद्दे मदरसा शिक्षा प्रणाली में वर्षों से स्पष्ट रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ, इस विधेयक का उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों को भी शामिल करना है। अब उत्तराखंड में गुरुमुखी और पाली भाषाओं के अध्ययन को भी आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। विधेयक यह भी सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को शुल्क, दान, अनुदान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग न हो।

उन्होंशने कहा, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के अपने संस्थान होने चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की हेराफेरी से मान्यता समाप्त हो सकती है। इन संस्थानों की निगरानी के लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। संस्थानों को कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

इसके साथ ही विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं होगी। संस्थानों को अपने धार्मिक पाठ्यक्रम पढ़ाने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते वे राज्य शिक्षा बोर्ड के निर्धारित मानकों का पालन करें और बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से न काटें। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष तक ने इस कानून का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मुस्लिम बच्चों को भी अवसर मिलेगा कि वे आईएएस, आईपीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ें।

उत्तराखण्ड की साहसिक पहलें

असल में यह विधेयक उस सोच का विस्तार है जिसे धामी सरकार ने पिछले वर्षों में लागू किया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना, धर्मांतरण विरोधी कानून को मजबूत किया गया और फर्जी साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि चलाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में नया विधेयक भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है।

इस पहल को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत

इस कदम को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार का वित्तीय सहयोग लगातार घट रहा है। योजनाएं पुनर्गठित हुईं, लेकिन मदरसों के लिए धनराशि 2014-15 में 194 करोड़ से घटकर 2024-25 में मात्र कुछ लाख तक सिमट गई। यह स्थिति बताती है कि अब केवल धन बांटने की नीति नहीं चलेगी। संस्थानों की जिम्मेदारी तय करनी होगी और बच्चों की शिक्षा को सर्वोपरि रखना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि धार्मिक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर रखने से बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए पहले उत्तराखण्ड सरकार ने अवैध मदरसों की छंटाई की और फिर नया कानून लाकर सभी अल्पसंख्यकों को समान अवसर दिया, जोकि एक दूरदर्शी नीति का परिचायक है। इससे शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, बच्चों को बेहतर अवसर मिलेगा और समाज में विश्वास बढ़ेगा।

जल प्रलय के सन्देश?

तनवीर जाफ़री

भारत के पंजाब राज्य को सबसे उपजाऊ धरती के राज्यों में सर्वोपरि गिना जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि यह राज्य खेती के लिये सबसे ज़रूरी समझे जाने वाले कारक यानी पानी के लिये सबसे धनी राज्य है। सिंधु नदी की पांच सहायक नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम इसी पंजाब राज्य से होकर बहती हैं। इन पांचों नदियों में केवल व्यास ही एक ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है शेष सतलुज, रावी, चिनाब और झेलम नदियाँ भारत से होते हुये पाकिस्तान में भीप्रवाहित होती हैं। यही नदियां जो पंजाब को उपजाऊ भूमि बनाने और यहाँ की संस्कृति का आधार समझी जाती हैं इन दिनों यही नदियां भारत से लेकर पाकिस्तान तक जल प्रलय का कारण बनी हुई हैं। इन नदियों के उफान पर होने का कारण जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार होने वाली तेज़ बारिश यहाँ तक कि अनेक स्थानों पर बादल फटने जैसी घटनाओं को माना जा रहा है।

दरअसल पिछले कुछ दिनों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के जलागम क्षेत्रों में असामान्य रूप से भारी बारिश हुई। कई ज़िले तो ऐसे भी थे जहाँ केवल एक ही दिन में पूरे एक महीने की बारिश दर्ज की गई। जैसे केवल अमृतसर और गुरदासपुर में 150-200 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज हुई। इससे शहरी जलनिकासी प्रणाली पूरी तरह फ़ेल हो गयी। दुर्भाग्यवश हमारे देश के अधिकांश राज्यों में बरसाती जल निकासी प्रणाली प्रायः फ़ेल ही रहती है। भ्रष्टाचारयुक्त निर्माण से लेकर सरकारी अम्लों की अकर्मण्यता व ग़ैर ज़िम्मेदार जनता द्वारा नाले नालियों में अवांछित वस्तुओं की डम्पिंग यहाँ तक कि मरे जानवर से लेकर रज़ाई गद्दे बोतलें प्लास्टक पॉलीथिन आदि सब कुछ नालों व नालियों में फ़ेंक देने जैसी ग़ैर ज़िम्मेदाराना प्रवृति, जल निकासी प्रणाली के फ़ेल होने में सबसे अहम भूमिका निभाती है।

एक ओर तो भारी बारिश व जलभराव उसके बाद भारत के सबसे विशाल भाखड़ा नंगल डैम, पोंग डैम रणजीत सागर डैम व शाहपुर कंडी जैसे डैम्स से अतिरिक्त पानी का छोड़ा जाना भी पंजाब की बड़े हिस्से की तबाही का कारण बन गया। इन डैम्स से पानी छोड़ना भी इसलिये ज़रूरी हो गया था क्योंकि इनमें इनकी क्षमता से अधिक जलभराव हो गया था। उदाहरण के तौर पर भाखड़ा डैम का जल स्तर 1,671 फीट तक पहुँच गया था तो पोंग डैम का जलस्तर भी अधिकतम से ऊपर चला गया था। इसी के परिणाम स्वरूप राज्य की सतलुज, ब्यास और रावी नदियाँ उफान पर आ गईं थीं। भारत से पानी छोड़ने के कारण ही पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में भी बाढ़ आई, जहाँ रावी, सतलुज और चेनाब नदियाँ प्रभावित हुईं। इस स्थिति के मद्देनज़र भारत ने पहले ही मानवीय आधार पर पाकिस्तान को तीन चेतावनियाँ जारी कर दी थीं।

भारतीय पंजाब के जो ज़िले इस भीषण जल प्रलय में प्रभावित हुये उनमें गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारन, फिरोज़पुर व फ़ज़िल्का के नाम ख़ासतौर पर उल्लेखनीय हैं जबकि लुधियाना और जालंधर में भी बढ़ का प्रभाव देखने को मिला। दर्जनों पुल टूट गये,सैकड़ों पशु बह गये अनेक वाहन तेज़ बहाव में समा गये। लाखों एकड़ फ़सल तबाह हो गयी ,तमाम मकान बह गये या क्षतिग्रस्त हो गये। दर्जनों जगह से हाईवे व मुख्य मार्ग बंद हो गये। और इस प्रलयकारी हालात से जूझने में कई जगह पंजाब का वह किसान स्वयं को असहाय महसूस करता दिखाई दिया जो हमेशा पूरी हिम्मत व हौसले के साथ दूसरों की सेवा सत्कार के लिये तत्पर दिखाई देता है। एक अनुमान के अनुसार राज्य के 500 से अधिक गांव डूबे गये इन गांवों में लगभग 6,600 से अधिक लोग फंसे थे। अमृतसर के रामदास क्षेत्र में रावी नदी का धुसी बांध टूट गया, जिससे 40 गांव डूब गए। इसी तरह गुरदासपुर में लगभग 150, कपूरथला में क़रीब 115, और अमृतसर में लगभग 100 गांव इस प्रलयकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुये। गोया इस बार की बाढ़ ने कृषि-प्रधान पंजाब की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। इस बाढ़ के चलते सैकड़ों घर, 300 से अधिक स्कूल अनेक सड़कें, पुल और बिजली लाइनें आदि क्षतिग्रस्त हो गयीं । अमृतसर में गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहिब डूब गया। कई जगह रेल यातायात बाधित हुआ अनेक ट्रेन्स कैंसिल कर दी गयीं। हाईवे टूटने व क्षतिग्रस्त होने के चलते 1,000 से अधिक सड़कें बंद कर गयीं । अकेले वैष्णो देवी में बारिश के चलते हुये भूस्खलन से 30 से अधिक मौतें होने की ख़बर है। अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहे उसके मुताबिक़ धान, गन्ना व मक्का की लगभग 1.5 लाख एकड़ फ़सल पूरी तरह डूब गई। पंजाब में लगभग 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि जलमग्न हो गयी। इन बाढ़ग्रस्त क्षत्रों के किसानों को सितंबर-अक्टूबर में होने वाली रबी की फ़सलों में भी नुकसान की आशंका बनी हुई है। पंजाब में आई बाढ़ से हुआ अरबों रुपये का यह नुक़सान खाद्य मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करेगा। बाढ़ और बारिश-संबंधी हादसों से भारत व पाकिस्तान में अनेक मौतें भी हुई हैं जबकि अनेक लोग लापता भी हो गए हैं।

इसी तरह हज़ारों पशुओं के बह जाने, मरने,बीमार पड़ने के साथ साथ उनके चारों की भी भारी कमी दर्ज की जा रही है। इन्हीं हालात में बीमारियों का भी ख़तरा बढ़ गया है। इससे पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।आपदा के इस समय में सेना एनडीआरएफ़ व एसडीआरएफ़ द्वारा 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाई गयी व उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने किया कोटद्वार बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण

सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी, मरीजों से ली फीडबैक

पथ प्रवाह,कोटद्वार

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण ने सोमवार को चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय (बेस अस्पताल), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालपानी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ीघाट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार ले रहे मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।श्रीमती ऋतु खण्डूडी ने बताया कि हाल ही में बेस चिकित्सालय को दो आर्थोपेडिक चिकित्सक, दो गायनी विशेषज्ञ और तीन एनेस्थीसिया विशेषज्ञ मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और मरीजों को अब बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है और कोटद्वार क्षेत्र के नागरिकों को उत्तम चिकित्सा सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

निरीक्षण के दौरान गंदगी पर नाराजगी

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते समय सफाई व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि ÷स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हर मरीज का अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।÷

यहां का भी किया निरीक्षण

इसके साथ ही उन्होंने लालपानी और गाड़ीघाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ से बातचीत कर मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और आवश्यक दवाइयों एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं पर सर्वे की रिपोर्ट पर जताई आपत्ति

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने एक प्राइवेट कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'नारी 2025' में देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों की सूची में शामिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा की एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स (एनएआरआई) से आयोग का कोई ताल्लुक नहीं है और यह पूरी तरह निजी सर्वे है।

निजी सर्वे का आधार, आयोग ने किया खारिज

बीते 28 अगस्त को दिल्ली में आयोजित एक निजी कंपनी के कार्यक्रम में 'पीवैल्यू एनालिटिक्स' द्वारा तैयार सर्वे के आधार पर यह पुस्तक जारी की गई। इसमें 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से जुड़े आंकड़े शामिल किए गए हैं। कुसुम कंडवाल ने कहा कि इतने सीमित आंकड़ों पर शहरों की सुरक्षा स्थिति तय करना गलत है और इससे देहरादून की छवि धूमिल होती है।

प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। किसी भी अप्रिय घटना पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा, देहरादून की महिलाएं भलीभांति जानती हैं कि यहां महिला सुरक्षा के लिए सरकार, शासन और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।÷ यह सर्वे एक निजी एजेंसी ने किया है। सर्वे की रिपोर्ट प्रमाणिक नही है। एजेंसी को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जायेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग का भी नहीं समर्थन

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर भी मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने भी इस सर्वे का समर्थन नहीं किया। कुसुम कंडवाल ने रहाटकर से फोन पर बातचीत कर पुष्टि की कि इस सर्वे और उसके आंकड़ों से राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई संबंध नहीं है।

आयोग तलब करेगा रिपोर्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने कहा कि वह इस सर्वे की पूरी रिपोर्ट तलब करेगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कंडवाल ने दोहराया कि महिला सुरक्षा को लेकर भ्रामक रिपोर्ट जारी कर देहरादून की छवि खराब करना निंदनीय है।

कलियर में उर्स मेले का आगाज, सुरक्षा के रहेंगे कड़े प्रबंध

पथ प्रवाह संवाददाता।

हरिद्वार, 01 सितंबर। हरिद्वार के पिरान कलियर में हजरत मखदूम अली अहमद साबिर साहब का 757वां पवित्र वार्षिक उर्स मेला सोमवार से शुरू हो गया। मेले को सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए मेले में लगे फ़ोर्स को एसपी देहात द्वारा ब्रीफ किया गया। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की व सीओ रुड़की मौजूद रहे।

मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु हरिद्वार पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम करते हुए मेले को 4 जोन और 13 सेक्टर में विभाजित किया गया है, और 24 अस्थायी पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया है। मेला क्षेत्र के करीब 100 स्थानों को सीसीटीवी से कवर किया गया है, ताकि असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। नहर घाट और बावन दर्रा पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए पीएसी आपदा राहत तैराक दल और जल पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। कलियर लंगरों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए 4 स्थानों पर फायर यूनिट की टीमें तैनात की गई हैं। पर्स मोबाइल और जेब कटने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जेब कतरा स्क्वाड और महिलाओं व किन्नरों के साथ छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए अलग से पुलिस स्क्वाड नियुक्त किया गया है। मेला क्षेत्र में बच्चों के गुम होने और खोए-पाए संपत्ति की तलाश व मिलान के लिए खोया-पाया केंद्र का गठन किया गया है।10 स्थानों पर अस्थाई बैरियर व 7 स्थानों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है और बड़े व भारी वाहनों को 4 से 9 सितंबर तक मेला क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

एक नजर

कृषि मंत्री गणेष जोशी को सौंपा ज्ञापन तो कृषि सहायकों को मिला आश्वासन

पथ प्रवाह, देहरादून/कृषि विभाग में कार्यरत कृषि सहायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्य की सभी 670 न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायक कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री ने प्रतिनिधियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए सकारात्मक रुख अपनाया और शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य

इस मौके पर कुशाल सेमवाल, ललित सिंह, कलावती, संगीता नौटियाल, प्रकाश राणा, बबलू शर्मा, सुभाष तोमर, कुलदीप सहित कई कृषि सहायक मौजूद रहे।

जगतोली दशजुल्या महोत्सव में लोकल उत्पादों की प्रदर्शनी, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता का मंच

संदीप बर्तवाल, रुद्रप्रयाग। अगस्त्यमुनि ब्लॉक के महड़ गांव में आयोजित जगतोली दशजुल्या महोत्सव इस बार खास रहा। ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत शिवशक्ति स्वायत सहकारिता द्वारा यहां स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मंच प्रदान किया। प्रदर्शनी में क्षेत्रीय दालें, धूपबत्ती, जूस, अचार, जैम समेत कई पारंपरिक व घरेलू उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन किया गया। महिलाओं के हाथों से बने इन उत्पादों को लोगों ने खूब पसंद किया और जमकर खरीदारी भी की। इससे जहां उत्पादों को नया बाजार मिला, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। जिला परियोजना प्रबंधक और यंग प्रोफेशनल्स ने भी इस आयोजन में भागीदारी कर महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणादायी हैं और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखते हैं।

धारचूला: एलागाड़ पावर हाउस टनल में मलबा गिरने से 19 मजदूर फंसे

8 सुरक्षित बाहर निकाले गए, 11 अंदर सुरक्षित

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़

धारचूला स्थित एनएचपीसी की जल विद्युत परियोजना के एलागाड़ पावर हाउस टनल के मुंह पर रविवार को अचानक मलबा आ जाने से टनल का प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। हादसे के समय टनल के भीतर कुल 19 कर्मी कार्यरत थे।

रेस्क्यू टीमों और बीआरओ ने तत्परता से काम करते हुए इमरजेंसी शाफ्ट का मलबा हटाकर आवाजाही बहाल कर दी। अब तक 8 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 11 कर्मी टनल के अंदर सुरक्षित बताए गए हैं। ये सभी पावर सप्लाई की ड्यूटी पर तैनात हैं और उनकी शिफ्ट सोमवार को बदली जाएगी।

अधिकारी मौके पर

घटना स्थल पर सेना के कर्नल, एनएचपीसी के महाप्रबंधक, एनडीआरएफ, ग्रिफ, बीआरओ के अधिकारी और धारचूला पुलिस की टीम मौजूद है। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव स्वयं हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

सुरक्षा इंतजाम और अपील

टनल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर न फैलाएं। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करने की अपील की है।

पहाड़ की खेती संकट में ~ बंदर-सूअर का आतंक, किसानों ने मांगा सोलर हूटर

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़

उत्तराखंड का पहाड़ खेती-किसानी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। खेतों में मेहनत से उगी फसलें बंदरों और जंगली सूअरों के हमले से उजड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि अब खेती बचाना उनके बस की बात नहीं रही। हालात ऐसे हैं कि किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे पलायन का खतरा और गहरा हो गया है।

फसलें उजाड़ रहे जंगली जानवर

किसानों का कहना है कि बंदरों की टोली खेतों में घुसकर सिर्फ अन्न ही नहीं खाती, बल्कि पौधों को उखाड़कर भी नष्ट कर देती है। जंगली सूअर रात के अंधेरे में आलू-मक्का जैसी पूरी फसल खोद डालते हैं। महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल जाती है।

पलायन की त्रासदी गहराई

ग्रामीणों ने कहा कि खेत ही सुरक्षित न हों तो खेती क्यों करें? यही सोच पहाड़ में पलायन को जन्म दे रही है।

गांव खाली हो रहे हैं और खेत बंजर। बुजुर्ग घरों में अकेलेपन की मार झेल रहे हैं।

सरकारी योजनाएँ नाकाफी

किसानों का आरोप है कि बंदरों की नसबंदी योजना धीमी और अप्रभावी है। सूअरों पर नियंत्रण की कोई ठोस योजना नहीं है। फसल बीमा में भी यह समस्या शामिल नहीं होती। वन्यजीव संरक्षण कानूनों के चलते किसान अपनी ही फसल की रक्षा नहीं कर पा रहे।

सोलर हूटर बना उम्मीद

ग्रामीणों ने कहा कि सोलर हूटर किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। यह उपकरण आवाज और रोशनी से जंगली जानवरों को खेतों से दूर रखने में कारगर है। मगर पहाड़ी किसानों की आर्थिक स्थिति इन्हें खरीदने की अनुमति नहीं देती। किसानों ने मांग की कि सरकार इन्हें अनुदान या मुफ्त उपलब्ध कराए।

किसानों की पुकार

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. किशोर कुमार पंत ने कहा, ÷यदि किसान खेती छोड़ देंगे तो पहाड़ सूना हो जाएगा। किसानों को सिर्फ सहारा चाहिए, ताकि वे अपनी मिट्टी और खेतों से जुड़े रह सकें।÷ किसानों का कहना है कि उनकी रक्षा करना केवल कृषि बचाना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और अस्मिता को बचाना है।

उत्तरकाशी को मिला निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष, रमेश चौहान ने संभाला दायित्व

विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन को बताया प्राथमिकता

ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, उत्तरकाशी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए रमेश चौहान ने सोमवार को विकास भवन लदाड़ी परिसर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) प्रशांत आर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। यह अवसर उत्तरकाशी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार कोई जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुआ है।

ऐतिहासिक रहा शपथ ग्रहण समारोह

शपथ ग्रहण समारोह में भारी जनसमूह की मौजूदगी ने माहौल को ऐतिहासिक बना दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दीं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाना ही पंचायत प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं

समारोह में विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, दर्जा राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने इसे उत्तरकाशी के लिए गौरव का क्षण बताया और निर्विरोध निर्वाचन को राजनीतिक सहयोग और सामंजस्य की मिसाल करार दिया।

एक नजर

स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा: पिथौरागढ़ में कनार का घी आकर्षण का केंद्र

जीवन सिंह बोहरा, पिथौरागढ़

जिलाधिकारी विनोद गिरि गोस्वामी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। सोमवार को डीएम कार्यालय प्रांगण में कनार गांव के प्रसिद्ध घी का विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सराहा और खरीदारी भी की।

कनार का घी बना पहचान

कनार गांव का घी अपने स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए पहले से ही मशहूर है। जिलाधिकारी की पहल से इसे प्रशासनिक स्तर पर पहचान और नया बाजार मिला है। इस मौके पर कई अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पहल ग्रामीण उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहन देने में मील का पत्थर साबित होगी।

ग्रामीणों की आजीविका को सहारा

इस प्रदर्शन से न केवल कनार गांव के लोगों को अपनी आजीविका मजबूत करने का अवसर मिलेगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों के लिए व्यापक मंच भी तैयार होगा। इससे उत्तराखंड के अन्य गांवों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे अपने विशेष उत्पादों को इसी तरह प्रस्तुत करें।

९ग्राम स्वराज की दिशा में कदम

जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि समय-समय पर ऐसे स्टॉल से खरीदारी कर ग्रामीणों का हौसला बढ़ाएं।

पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को दोपहर 12ः30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रूपये भी हस्तांतरित करेंगे, जिससे इसका औपचारिक रूप से शुरुआरंभ होगा।

यह सहकारी संस्था जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर आसान वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तर के फेडरेशन इसके सदस्य होंगे। इस योजना के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा फंडिंग की जाएगी।

जलभराव की निकासी के डीएम मयूर दीक्षित ने राजस्व और सिंचाई विभाग को दिये निर्देश

पथ प्रवाह संवाददाता। हरिद्वार, 01 सितंबर। अहमदपुर ग्रांट एवं उत्तम डिस्टिलरी, सहदेवपुर गांव के किसानों के खेतों एवं आसपास की कॉलोनियों में हो रहे जल भराव की समस्या के निदान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साकारात्मक पहल की है। उन्होंने निकासी एवं उसके उचित समाधान के लिए जिला कार्यालय सभागार में सम्बन्ध अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की।

बैठक में ग्राम अहमदपुर ग्रांट उत्तम डिस्टिलरी, सहदेवपुर ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया कि क्षेत्र में वर्षा के पानी के कारण उनके खेतों एवं आस पास के आवासीय कॉलोनीयों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके लिए उन्होंने ने जल निकासी के समाधान के लिए उचित प्रबंधन किये जाने की मांग की। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी हरिद्वार, संयुक्त मजिस्ट्रेट रूड़की एवं अधीशासी अभियंता सिंचाई से उक्त गांवों में हो रहे जलभराव के स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली। जिस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि सम्बन्धित गांव के क्षेत्र में एक सिंचाई विभाग का नाला है एवं दो राजस्व विभाग के नाले है। जिनके माध्यम से क्षेत्र में हो रहे जल भराव कि निकासी कि जा सकती है। बैठक में जिलाधिकारी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रूड़की, उपजिलाधिकारी हरिद्वार एवं अधीशासी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिये है कि सिंचाई विभाग उत्तरप्रदेश के अधीन नाले को दुरस्त कराया जाए तथा राजस्व विभाग के अधीन जो दो नाले है उनकी सफाई के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही तत्परता से करने के निर्देश दिये ताकि उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे जलभराव की स्थिति का निदान किया जा सके। उन्होंने सिंचाई विभाग एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षेत्र में हो रहे जल भराव के स्थाई समाधान के लिए किये जाने वाले कार्य के लिए सिंचाई विभाग उत्तरप्रदेश के माध्यम से आंकलन प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा ताकि जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को निदान मिल सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त दीपेन्द्र सिंह नेगी, संयुक्त मजिस्ट्रेट रूड़की दीपक आर सेठ, उपजिलाधिकारी हरिद्वार जितेन्द्र कुमार, अधीशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, अधीशासी अभियंता लोनिवि दीपक कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, ग्राम प्रधान और ग्रामीण मौजूद थे।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी के आदेशों पर बद्रीनाथ व हेमकुंड यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित

संदीप बर्तवाल, चमोली

मुख्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की चेतावनी के बाद चमोली जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए श्री बद्रीनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को 1 सितंबर से 5 सितंबर तक अस्थायी रूप से रोक दिया है।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जारी आदेश के अनुसार आगामी दिनों में जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। बारिश से नदियों-नालों में जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन की आशंका के चलते यात्रियों एवं स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। डीएम संदीप चमोली ने बताया कि मार्गों पर आवागमन अवरुद्ध होने और जनहानि की आशंका को देखते हुए यात्रा रोकने का निर्णय आवश्यक हो गया। उन्होंने पर्यटन विभाग, आपदा प्रबंधन, पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की सभी टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित जिलों के अधिकारियों को भी सूचित कर आवश्यक प्रबंध करने को कहा गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे फिलहाल यात्रा पर न निकलें और मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें। गौरतलब है कि मानसून सीजन में बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अक्सर भूस्खलन और अवरोध की स्थिति बनती रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए आदेश का पालन सभी को करना आवश्यक होगा।

उत्तरकाशी में लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित, मार्ग अवरुद्ध होने पर प्रशासन अलर्ट

सुरेंद्र पाल सिंह, उत्तरकाशी। जनपद में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। जिले के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर पेड़, मलबा और पत्थर गिरने से यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों की टीमों को मौके पर भेज दिया है। मार्गों को खोलने के लिए श्रमिकों और भारी मशीनों की तैनाती की गई है तथा अवरुद्ध सड़कों को जल्द से जल्द सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार बारिश से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बहुत जल्द यातायात बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों और यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।

उत्तरकाशी आपदा संभावित जिला होने के कारण प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बंद पड़े मार्गों से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि प्रशासन का दावा है कि लगातार प्रयासों से हालात जल्द ही सामान्य कर दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि गंगोत्री, बड़कोट, पुरोला, जानकीचट्टी और इनके आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश, बिजली के साथ तूफान तथा अत्यधिक तीव्र बारिश होने की संभावना है। इस पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

एक नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों को हर संभव मानवीय मदद और राहत देने का कहा

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में रविवार देर रात आए 6.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान में आए भूकंप से हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय मदद और राहत देने के लिए तैयार है। इस आपदा में जान-माल की भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भूकम्प का सबसे ज्यादा असर कुनर और नंगरहार प्रांत में रहा , जहां बड़ी संख्या में घर ढह गए और कई लोग मलबे में दब गए। तालिबान प्रशासन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक मृतकों और घायलों की संख्या और बढ़ सकती है।राहतकर्मी और स्थानीय लोग पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे। हेलीकॉप्टरों की मदद से कई गंभीर घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया गया, जबकि राहत टीमें दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में भी भेजी गईं हैं।

चुघ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बांग्लादेशी घुसपैठियों से नज़दीकी का लगाया आरोप

कांग्रेस पाक आईएसआई की साझेदार से कम नहीं

पटना/दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने सोमवार को बिहार में राहुल गांधी की पदयात्रा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह तथाकथित फोटो-ऑप पदयात्रा सिर्फ कुछ इण्डी गठबंधन के गुटों के साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की रक्षा करने का अभियान है। अपने बयान में चुघ ने सवाल उठाया कि विपक्ष के नेता (एलोपी) जैसे संवैधानिक पद पर आसीन राहुल गांधी किस नैतिक आधार पर देशविरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं और अवैध घुसपैठियों के हित साधने में लगे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की उस पहल की सराहना की, जिसके तहत मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर करने की कार्रवाई की जा रही है। चुघ ने कहा कि पूरा इण्डी गठबंधन सिर्फ वोटों की सस्ती राजनीति के लिए देशविरोधी माहौल बनाने पर तुला हुआ है। चुघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी की पावन छवि पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह न केवल पूरे देश के लिए शर्मनाक है, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को भी कलंकित करता है। चुघ ने आगे कहा कि लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिश्ते मज़बूत करने की राहुल गांधी की कोशिशें कांग्रेस की देशविरोधी मानसिकता को उजागर करती हैं। बिहार और बंगाल में बांग्लादेश समर्थक नैरेटिव को बढ़ावा देना इसका ताज़ा उदाहरण है।

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर एक मेट्रो में खराबी आई, बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा

नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर एक मेट्रो में खराबी आ गई। इसके कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्लू लाइन के अलग-अलग स्टेशनों पर बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। दरअसल, ब्लू लाइन पर मंडी हाउस से नोएडा जाने वाली मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई। इसके कारण पूरी मेट्रो ट्रेन को खाली कराया गया। मंडी हाउस से नोएडा जाने वाले पूरे मेट्रो रूट पर स्टेशनों पर फंसे यात्री मेट्रो नहीं आने की शिकायत करते नजर आए।

ब्लू लाइन पर मेट्रो नहीं आने के कारण हजारों की संख्या में यात्री विभिन्न स्टेशनों में फंस गए। कई यात्रियों ने काफी देर से मेट्रो नहीं आने की शिकायत की। मेट्रो नहीं आने से विभिन्न स्टेशनों पर लोगों की भीड़ को संभालना भी मेट्रो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया।

गुरुग्राम में तेज बारिश से कई इलाकों में भारी जलजमाव

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं गुरुग्राम में इतनी तेज बारिश हुई कि कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया। वहीं नोएडा और आस-पास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गुरुग्राम में बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे थे। ऑफिस से घर जाने वाले इस दुविधा में थे कि आखिर इतने पानी में घर कैसे जाएंगे। गोल्फ रोड पर पूरा पानी भरा हुआ था।

भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के उद्देश्य से आयोजित 'सेमीकॉन इंडिया – 2025' का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के उद्देश्य से आयोजित 'सेमीकॉन इंडिया - 2025' का उद्घाटन करेंगे। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला यह तीन दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को एक बयान जारी इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी 2 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे यशोभूमि में 'सेमीकॉन इंडिया - 2025' का उद्घाटन करेंगे। वह 3 सितंबर को सुबह लगभग 9:30 बजे सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसमें सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, सेमीकंडक्टर फैब और उन्नत पैकेजिंग परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन आदि पर सत्र होंगे।

डॉ. आशुतोष सयाना बने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के नियमित प्राचार्य

नवीन चौहान, पथ प्रवाह

उत्तराखण्ड शासन ने डॉ. आशुतोष सयाना को राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर का नियमित प्राचार्य नियुक्त कर दिया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए।

डॉ. सयाना इससे पहले प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में निदेशक (2015 से अब तक) और दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में प्राचार्य (2019 से 2024) के पद पर कार्य कर चुके हैं। जनरल सर्जरी, ट्रॉमा केयर और मिनिमल एक्सेस सर्जरी के विशेषज्ञ डॉ. सयाना का चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक विकास में विशेष योगदान माना जाता है।

पूर्व प्राचार्य डॉ. सी.एम.एस. रावत के बाद वह अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत थे। अब शासन ने उन्हें नियमित प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपकर संस्थान को एक अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व दिया है। उम्मीद की जा रही है कि उनके मार्गदर्शन में कॉलेज में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य और अधिक सुचारू रूप से संचालित होंगे।

शैक्षणिक एवं पेशेवर सफर

डॉ. सयाना ने 1994 में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर से एमबीबीएस और 1999 में केजीएमसी, लखनऊ से एमएस (जनरल सर्जरी) की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दीं।

वह एचएनबी उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून में रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक रहे। दिल्ली के कई प्रमुख अस्पतालों में सेवाएं देने के साथ ही उनके शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत हो चुके हैं। विभिन्न परिषदों में पदभार संभालते हुए उन्होंने चिकित्सा शिक्षा को मजबूती दी है।

डॉ. सयाना का संकल्प

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी देने के लिए मैं मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और शासन का आभारी हूं। गढ़वाल क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। मेरा संकल्प है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को देश के श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजों में शामिल किया जाए।

– डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर

आईसीसी ने महिला एकदिवसीय विश्व कप के लिए पुरस्कार राशि में चारा गुना वृद्धि की

दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत में 30 सितंबर से दो नवंबर तक होने वाले आगामी महिला एकदिवसीय विश्वकप के लिए पुरस्कार राशि में चार गुना से अधिक की वृद्धि की है। आईसीसी द्वारा आज की गई घोषणा के अनुसार, न्यूजीलैंड में 2022 में खेले गए इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में कुल पुरस्कार राशि 35 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 30.80 करोड़ रुपये) थी। जिसे इस बार बढ़ाकर कुल 138.8 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 117.74 करोड़ रुपये) कर दिया है। यह राशि 2023 में होने वाले पुरुष एकदिवसीय विश्व कप के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि एक करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 करोड़ रुपये) से भी अधिक है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कहा, यह घोषणा महिला क्रिकेट के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पुरस्कार राशि में यह चार गुना वृद्धि महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इसके दीर्घकालिक विकास के प्रति हमारी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा संदेश सरल है, महिला क्रिकेटरों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनेंगी तो उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाएगा। आईसीसी ने टूर्नामेंट के प्रत्येक चरण के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। विश्वकप विजेता को अब 44.8 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 39.42 करोड़ रुपये) मिलेंगे। यह 2022 में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को मिली 13.2 लाख अमेरिकी डॉलर (11.62 करोड़ रुपये) की राशि से दोगुना से अधिक है। उपविजेता टीम को 22.4 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 19.71 करोड़ रुपये) मिलेंगे। हारने वाले दोनों सेमीफाइनलिस्टों को 11.2 लाख अमेरिकी डॉलर (9.86 करोड़ रुपये) मिलेंगे।

ग्रुप-स्टेज में प्रत्येक जीत के लिए विजेताओं को 34,314 अमेरिकी डॉलर (30.2 लाख रुपये) मिलेंगे। पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को सात लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 6.16 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जबकि सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को 2,80,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.46 करोड़ रुपये) मिलेंगे।

धराली आपदा पीड़ितों की मदद के लिए शिक्षकों का सराहनीय कदम, अब तक 3.19 लाख का अंशदान

ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

धराली/उत्तरकाशी। धराली आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए जिले के साथ ही अन्य जनपदों के शिक्षकों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तरकाशी के आह्वान पर चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक ?3,19,743 की राशि अंशदान स्वरूप प्राप्त हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी राजकीय शिक्षक संघ भटवाड़ी के अध्यक्ष मनोज परमार को सौंपी गई है। वे प्रतिदिन सहयोगकर्ताओं की सूची अपडेट कर शिक्षक समूहों में साझा कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभियान में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल जनपदों के शिक्षकों ने योगदान दिया है।

ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास ही मेरा लक्ष्य:भाजपा नेता सुबोध राकेश

पथ प्रवाह, बहादराबाद

ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के रुहालकी किशनपुर गाँव में चौहान समाज ने भाजपा नेता सुबोध राकेश का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर समाज के लोगों ने 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने सुबोध राकेश की कार्यशैली देखी है, जो 24 घंटे क्षेत्र की सेवा में

समर्पित रहते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुबोध राकेश ने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को बदहाली से निकालने के लिए वह दिन-रात कार्य करेंगे। मुख्य मार्गों का निर्माण और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक स्थानों पर नाले बनवाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर अंकित कुमार, कुलजीत चौहान, उधम सिंह, संजीव सिंह, राजीव, प्रवीण कुमार, ऋषिपाल सिंह, दिनेश चौहान, चंदन सिंह, बलदेव सिंह, सतेंद्र चौहान (मिक्का), प्रदीप चौहान, अतुल कुमार, ओमीचंद, राजू दाल वाला, दीपक चौहान, अशोक, पंडित गौतम समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बिहार मतदाता सूची, दावे या आपत्तियां एक सितंबर बाद भी : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मसौदा मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूर्व निर्धारित समय सीमा (1 सितंबर) के बाद भी राज्य के निवासियों के दावे या आपत्तियां स्वीकार करने की चुनाव आयोग को सोमवार अनुमति दे दी।

इस साल जून में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बिहार में मसौदा मतदाता सूची तैयार करने का शुरू किया गया ।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अनुमति देते हुए चुनाव आयोग की इस दलील पर गौर किया कि नामांकन (इस साल निर्धारित विधानसभा चुनाव) की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए सभी दावों या आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम द्वारा दावे और आपत्तियाँ दायर करने की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ाने के लिए दायर आवेदनों पर विचार करते हुए यह अनुमति दी।

शीर्ष अदालत के समक्ष चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी कहा कि दावे या आपत्तियाँ एक सितंबर की समय सीमा के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। मतदाता सूची को अंतिम

रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा।

अधिवक्ता द्विवेदी ने आश्वासन दिया कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी शामिल या हटाएं गए नामों को जांच प्रताल के बाद अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा।

न्यायालय ने आपत्तियाँ दर्ज कराने में संबंधित व्यक्तियों की सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती का भी निर्देश दिया। साथ ही, राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय होने को कहा। पीठ के समक्ष श्री द्विवेदी ने कहा कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 फीसदी ने अपने फॉर्म दाखिल कर दिए हैं। मसौदे से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं में से, केवल 33,326 लोगों और 25 दलों के माध्यम से दावे प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हटाए गए नामों के लिए 1,34,738 आपत्तियाँ दायर की गई हैं। अधिवक्ता ने कहा कि यह अजीब है कि राजनीतिक दल मसौदा सूची से मतदाताओं को हटाने की मांग करते हुए आपत्तियाँ दायर कर रहे हैं, न कि शामिल करने के लिए कोई दावा।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को आदेश दिया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन लोगों को मतदाता सूची के प्रारूप से बाहर रखा गया है, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार** (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालय: 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन–249408** (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई– www.pathpravah.com